



निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है,  
मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है, मूर्ख  
लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग  
मेहनती -गौतम बुद्ध

## राष्ट्र की अखंडता और अनेकता

तिरंगा हमारे राष्ट्र की अखंडता और अनेकता में एकता का गौरवमय प्रतीक है, उसे ही टकराव और हिंसा की आवाज बना दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कासगंज में दोनों तरफ गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा लहराने का जश्न जारी था। एक मोहल्ले की सड़क पर कुर्सियां लगी थीं और स्तंभ खड़ा था, जिस पर तिरंगा लहराया जाने वाला था। दूसरी ओर से कुछ बाइक सवारों की तिरंगा यात्रा निकल रही थी। उनकी जिद थी कि यात्रा उसी सड़क से निकलेगी तो दूसरी ओर कार्यक्रम संपन्न करने की मोहल्लत चाहिए थी। तनातनी बढ़ने की ओर भी वजहें बताई जा रही हैं। लेकिन सबाल है कि अगर मकसद गणतंत्र और तिरंगे के प्रति आस्था ही जाहिर करना था तो झंडोत्तोलन कायक्रम पहले हो जाता या तिरंगा यात्रा दूसरी राह से गुजर जाती या पिर यात्रा गुजर जाने देने के बाद ही झंडोत्तोलन होता तो क्या फर्क पड़ जाता? तिरंगे के प्रति सम्मान तो पिर भी जाहिर किया जा सकता था। इसी से संकेत मिलता है कि समाज में कैसी प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। जाहिर है, ये विघटनकारी प्रवृत्तियां न हमारे गणतंत्र के लिए अच्छी हैं, न तिरंगे की शान के लिए। इसलिए ऐसे रुझानों पर अंकुश लगाना जरूरी है। यहीं सरकार और सियासी दलों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पिर सत्तारूढ़ राजनैतिक बिरादरी का तो दायित्व कुछ ज्यादा ही होना चाहिए कि समाज में ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा न मिले। लेकिन राजनैतिक दल अपने इस दायित्व के प्रति अधिक सचेत नजर नहीं आते। आखिर तिरंगा यात्रा सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े संगठन निकाल रहे थे और बाद में सभा-जुलूसों में स्थानीय विधायकों की शिरकत की भी खबरें आई। लेकिन अगर प्रशासन पहले ही ऐतियातन कदम उठा चुका होता तो शायद इस हिंसा से बचा जा सकता था। प्रशासन संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर तिरंगा यात्रा का रूट बदलवा सकता था या पिर झंडोत्तोलन कार्यक्रम को ही कहीं और करने को कह सकता था। लेकिन अप्सोस!

प्रशासन अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहा, राजनैतिक दलों ने अपना दायित्व नहीं निभाया। नतीजा यह हुआ कि कुछ बेक्षूर लोगों की जान चली गई और सार्वजनिक-निजी संपत्तियां आग के हवाले कर दी गईं। अब भी वक्त है कि सरकार इस आग को दूसरे इलाकों में फैलने से रोके, कासगंज में शांति बहाली के लिए शरारती तत्वों पर अंकुश लगाए। तभी हमारे गणतंत्र और तिरंगे की शान भी कायम रहेगी।

## “रिवार्ड वर्क,

काबुल (अफगानिस्तान की राजधानी) में हुआ भयानक विस्फोट दुनिया भर के लिए आतंकवादियों की ओर से दिया गया यह खतरनाक संदेश है कि उनको खत्म करने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही। जितनी भारी संख्या में लोग मरे एवं घायल हुए उससे यह हाल के समय का सबसे बड़ा हमला हो गया है। तालिबान यदि इसकी जिम्मेवारी न लेता तो भी संदेश की सुई उसी की ओर जानी थी। 20 जनवरी को भी तालिबान ने काबुल के एक होटल पर हमला किया था, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। पिछले साल मई में जर्मन दूतावास के निकट तालिबान ने विस्फोट करके 150 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। उसके बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यहां भी जिस इलाके को विस्फोट के लिए चुना गया वहाँ भारतीय काउंसलर कार्यालय, यूरोपीय संघ के कार्यालय, स्वीडन एवं हॉलैंड के दूतावास हैं। इससे ऐसा लगता है कि इस बार भी तालिबानों के निशाने पर विदेशी ही रहे होंगे। वस्तुतः जिस एंबुलेंस में विस्फ्रेटक लदा था उसमें एक मरीज को अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर आतंकवादी एक चेकपोस्ट पार कर कर गए थे, लेकिन दूसरे चेकपोस्ट पर उनका पता चल गया एवं वही उन्होंने विस्फोट कर दिया। विस्फोट इतना बड़ा था कि दो किलोमीटर के दायरे में स्थित इमारतों की खिड़कियां हिल गईं और विस्फोट स्थल के पास की कम ऊँचाई के ढांचे ध्वस्त हो गए। विस्फोट के लिए एंबुलेंस का इस्तेमाल करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इस हमले के बाद एक-एक एंबुलेंस संदेह के धेर में आ जाएगा। यह निंदनीय है। किंतु आतंकवादियों को इससे क्या लेना-देना। अफगान गृह मंत्रालय के प्रबक्ता ने इसे तालिबान संबद्ध हक्कानी नेटवर्क की कारणजारी बताया है। जबसे अमेरिका ने पाकिस्तान पर तालिबानों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ाया है और अफगानिस्तान स्थित अपने सैनिकों की संख्या में बढ़ातरी की घोषणा की है तबसे हक्कानी नेटवर्क विदेशियों के विरुद्ध कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया है। हक्कानी और अफगानी तालिबानों के बीच तालमेल भी है। अब देखना है उस चुनौती का सामना हम कैसे करते हैं?

सत्संग  
आशा और निराशा

मनुष्य का जीवन आशा और निराशा का मिश्रण है। कभी हम यह सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन दूसरे ही पल हमें अपनी ही सफलता संदिग्ध लगने लगती है और पिछ हम किंतु-परंतु के फेर में पड़ जाते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यदि हम आशावान बनकर सफलता के प्रति आसक्त हैं, तो हम हर हाल में सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम निराशा के भवंतजाल में फँसकर यह चिंता करने लगेंगे कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं, तो हमारी सफलता भी संदिग्ध जाएगी। हमारी हार और जीत को हमारा मन और मस्तिष्क ही तय करता है। हमारे पास कई ऐसे लोग भी आते हैं, जो कहते हैं कि गुरु जी, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब होते हैं, पिछ अचानक से लक्ष्य हमसे काफ़ी दूर चला जाता है। कभी-कभी जरूर ऐसा होता है कि हम पूरी उम्मीद और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में भी हमें आशा का साथ नहीं ढोड़ना चाहिए। जब आप अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखते हैं, तो आप स्वतः ही अपने लक्ष्य को अपने करीब पाते हैं। हमारे जीवन में बारी-बारी से सुख-दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हमें सहज बने रहना चाहिए। जीवन जीने की कला यही है कि जब हमारे जीवन में सुख आएं तो हमें जी भर के हंस लेना चाहिए और जब दुख आएं तो उन्हें हँसी में उड़ा देना चाहिए। समय चाहे सुख वाला हो या दुख वाला, दोनों ही बीत जाते हैं, इसलिए हमें सुख में अपना संयम और दुख में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। सुख-दुख, अंधेरे और प्रकाश की तरह हैं। जिस तरह हर गत की सुबह होती है। उसी तरह सुख-दुख के साथ भी ऐसा ही होता है। जब लोग दुख में होते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख आने पर वे भगवान को भूल जाते हैं। कवि कहता है कि दुख में भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में उसे कोई याद नहीं करता। अगर लोग सुख में भी भगवान को याद करें तो उन्हें दुख आएगा ही नहीं। दरअसल, भगवान को याद करते हुए जब हम अपने निवेदन में उसकी प्रार्थना करते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रार्थना से हमें बल, विश्व, प्रेरणा, आशा और मार्गदर्शन मिलता है।

# “नेचुरल पार्टी आफ करप्शन”

लोक सभा और बाद के विधान सभा चुनाव भाजपा के साथ नहीं लड़ेगी, मगर जिस भाजपा से वह इतनी नफ़्त करती है अभी उसके नेतृत्व में राज्य और केंद्र में सरकार में बनी रहेगी। उन्हें छोड़ने का साहस नहीं कर पा रही है। इसलिए राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि शिवसेना का यह तलाक धमकी ज्यादा है। धमकी के जरिये वह अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाना चाहती है। सरकार में बने रहना इसका संकेत है। सवाल उठता है कि आखिरकार भाजपा और शिवसेना के बीच झगड़े की वजह क्या है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा को हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रखना चाहती थी।

सतीश पेडणोकर

लाक तलाक तलाक। यह कहकर भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भाजपा को तलाक दे दिया। यूं तो भाजपा के बहुत से सहयोगी दल रहे हैं, जिनके साथ उसका गठजोड़ होता है। मगर भाजपा और शिवसेना का नाता खास है। दोनों कहते थे कि दोनों का गठबंधन चुनावी नहीं वैचारिक है क्योंकि दोनों की विचारधारा हिन्दुत्व ही है। दोनों की यह वैचारिक एकता ने दोनों को साथ भले ही रखा हो मगर यह रिश्ता मनमुटाव और प्रतिष्पर्धा का भी था। मनमुटाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार गठबंधन टूट गया। मगर शिवसेना ने यह तलाक बहुत अजीब तरीके से दिया। उसने कहा वह 2019 में लोक सभा और बाद के विधान सभा चुनाव भाजपा के साथ नहीं लड़ेगी, मगर जिस भाजपा से वह इतनी नफरत करती है अभी उसके नेतृत्व में राज्य और केंद्र में सरकार में बनी रहेगी। उन्हें छोड़ने का साहस नहीं कर पा रही है। इसलिए राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि शिवसेना का यह तलाक धमकी ज्यादा है। धमकी के जरिये वह अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाना चाहती है। सरकार में बने रहना इसका संकेत है। सवाल उठता है कि आखिरकार भाजपा और शिवसेना के बीच झगड़े की वजह क्या है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा को हमेशा दूसरे दर्जे पर ही रखना चाहती थी। पिछले कुछ वर्षों में यह खबाब टूट जाने के कारण ही शिवसेना और भाजपा के संबंध बिगड़े और अब शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। तीन दशक पहले रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान शिवसेना-भाजपा ने हिन्दुत्व के मुद्दे पर गठबंधन किया था। चूंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी थी, इसलिए लोक सभा चुनाव में भाजपा को ज्यादा सीटें देने और क्षेत्रीय दल होने के कारण विधान सभा चुनाव में शिवसेना को ज्यादा सीटें दिए जाने का फैसला हुआ था। शिवसेना राज्य की राजनीति में भाजपा को हमेशा छोटे भाई जैसा बर्ताव करती रही। शिवसेना को यह डर सताता रहा कि बराबरी की सीटों पर लड़कर भाजपा ज्यादा सीटें लाएगी और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा करेगी। इसलिए गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने महाराष्ट्र में लोक सभा और विधान सभा चुनाव आूकेले लड़ने के फैसले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी सहयोगी दलों को महत्व नहीं दे रही है इसलिए अब पार्टी ने अपनी भविष्य की रणनीति तय कर ली है। शिवसेना भाजपा पर कोई भी आरोप लगाए मगर भाजपा उसे खतरा नहीं मानती। भाजपा को लंबे समय से अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि शिवसेना सरकार में शामिल होने के बावजूद विपक्ष की तरह बर्ताव कर रही थी। वह केंद्र और गज्जु मरकाप पर लगातार लौटाकर्मी कर्ती रखती थी। पिछले कुछ

विषपक्षी एकता में शामिल करने के लिए ममता उद्घव से मिली थी। भाजपा को यह भी लगता है कि शिवसेना अपनी सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाने के लिए यह सब कर रही है। दरअसल, शिवसेना भाजपा दोनों ही हिन्दुत्ववादी दल है इसलिए वे साथ-साथ हैं, मगर उनमें कट्टी प्रतिस्पर्धा अपना प्रभाव बढ़ाने की है और पिछले कुछ समय में भाजपा का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि शिवसेना का हिन्दुत्व भावनात्मक ज्यादा और बौद्धिक कम है। संघ के पूर्व सरसंघचालक के एस मुदर्शन ने कहा था “शिवसेना का हिन्दुत्व भावनात्मक धरातल पर है। वैचारिक अधिष्ठान के क्षेत्र में उसने विशेष कुछ नहीं किया। दरअसल, शिवसेना ने हिन्दुत्व के भावनात्मक मुद्दे भले ही उठाए हो मगर उसे फैलाने की सुनियोजित कोशिश नहीं की। संघ और भाजपा ने ऐसी कोशिश की जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। शिवसेना उसके साथ लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। वैसे शिवसेना का मुद्दा केवल हिन्दुत्व ही नहीं है। वरन् उसके दो मुद्दे हैं। हिन्दुत्व और मराठी मानुस; किंतु राज ठाकरे की राजनीतिक दुर्गति से सप्तष्ठ हो गया



से बचा सकते हैं। भाजपा को एनसीपी के संभावित समर्थन के कारण शिवसेना सौदेबाजी नहीं कर पाइ। एनसीपी और भाजपा के इस रिश्ते से उसके सीने पर सांप ज़स्तर लोटे रहे। लेकिन भाजपा को अगला चुनाव एनसीपी के साथ लड़ा चुनाव पड़ सकता है। यह स्थिति भाजपा के लिए बेहद शर्मनाक होगी। एनसीपी के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। मोदी ने अपने चुनाव अभियान में उसे “नेचुरल पार्टी आफ करप्शन” कहा था। चुनाव में यदि भाजपा को अकेले नहीं लड़ा है तो उसे एनसीपी के साथ गठबंधन करना होगा। अब अगर एनसीपी के साथ चुनाव लड़ा है तो उसके मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामलों से बरी करना होगा, जिससे भाजपा की छीछलेदार होगी। वैसे शिवसेना के इस फैसले से भाजपा और शिवसेना दोनों को ही नुकसान होगा। भाजपा अपने बूरे बहुमत नहीं ला सकती क्योंकि हिन्दू वोटों में लहर के कारण वह इतनी जीत नहीं होगा। पिछले चुनावों जैसी विजय सेना भी एक ताकत के रूप में सभा चुनाव लड़ेगी तो मुंह के बल महाकाष्ठ में उसका प्रभाव है ही नोचेना “मुंगेरी लाल के हसीन और शिवसेना के बारे में कहा जाता है। कहावत है न मध्ये और नहीं

चलते चलते

## विज्ञान और योग

स्कूलों में बच्चों के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। हालांकि इसे शारीरिक दंड के जरिये लागू करना बहुत ही अमानवीय और आपात्तिजनक है। लैंकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाँबुआ जिले के एक सरकारी विद्यालय में ऐसा ही कुछ हुआ है। यहां 12 साल की एक छात्रा को शिक्षक ने होमर्कर्प पूरा न करने की अजीब सजा दी। शिक्षक ने छात्रा को उसके क्लास की चौदह छात्राओं से लगातार छह दिन तक थप्पड़ लगावाए। इस संवेदनहीन व्यवहार के चलते छात्रा न केवल बीमार पड़ गई बल्कि अब डर के कारण उसने स्कूल जाने से भी मना कर दिया है। यह सब कुछ उस राज्य में हुआ, जिनकी पार्टी की अनोखी मुहिम है “पढ़ेंगी बेटी, तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटी।” नरेन्द्र मोदी सरकार का यह अभियान

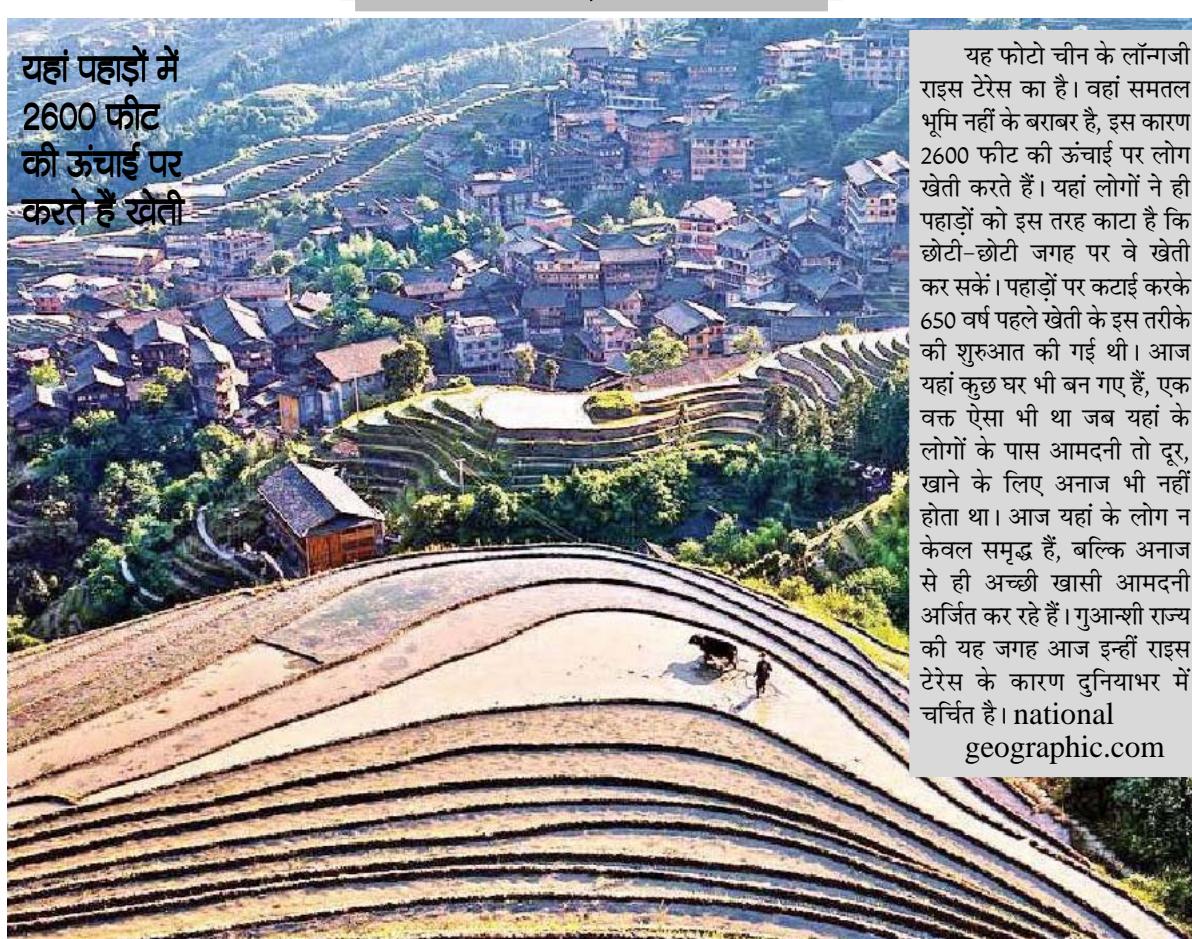
मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जात्यांग जाबुआ जिले के एक सरकारी विद्यालय है। यहाँ 12 साल एक छात्रा को शिक्षक ने होमवर्क पूछ करने की अजीब सजा दी। शिक्षक छात्रा को उसके कलास की चौदह छात्र से लगातार छह दिन तक थप्पड़ लगाया। मुंह चिदाता नजर आ रहा है। जब तक बेटी और सुरक्षित नहीं होगी, तब तक देश और सभी बदलाव नहीं आ सकता है। मगर स्कूल प्रबंध एसी घटिया हरकतों से अच्छी योजनी की तस्वीर ही दिखती है। साफ तौर पर यह विद्यालय की नाकामी है। विद्यालय को तो छात्र-छात्रा प्रति संवेदनशील होना चाहिए। किसी भी तरह सजा का बच्चों के मन पर गहरा असर पड़े। पूर्व में देश के अन्य विद्यालयों के शिक्षक की के चलते बच्चों द्वारा आत्महत्या करने की भी सामने आई है। ऐसे में हर विद्यालय

इल्म होना चाहिए कि सखी करना या १  
पैदा करना या किसी तरह का दंड देना कि  
बच्चे को उनसे कितना दूर ले जाएगा ? दुर्भागा  
से स्कूलों में कूर या असामान्य सजा पर प्रतिवार  
लगाने का कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। शिक्षण  
पर राष्ट्रीय नीति केवल यह कहती है कि शारीरिक  
दंड अनुज्ञय नहीं हैं।

स्वाभाविक तौर पर एक गुरु या शिक्षक  
छात्र के लिएआदर्श मॉडल होता है। बच्चे  
आमतौर पर अपने शिक्षक का अनुकरण करते  
हैं। उन्हें अपने छात्रों से धैर्य से निपटना, सल्ला  
देना और जीवन के हर क्षेत्र मसलन; शिक्षाविद्या  
खेल, संगीत और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट  
के लिए मानदर्शन करना चाहिए। शिक्षकों  
यह जानना बेहद जरूरी है कि आज की पीढ़ी  
जागरूक है। दूसरा; स्कूल मैनेजमेंट की भूमिका  
पारदर्शी होनी चाहिए, तभी उनकी गरिमा बढ़ती

फोटोग्राफी...

यहां पहाड़ों में  
2600 फीट  
की ऊंचाई पर



यह फोटो चीन के लॉनाजी राइस टेरेस का है। वहां समतल भूमि नहीं के बराबर है, इस कारण 2600 फीट की ऊँचाई पर लोग खेती करते हैं। यहां लोगों ने ही पहाड़ों को इस तरह काटा है कि छोटी-छोटी जगह पर वे खेती कर सकें। पहाड़ों पर कर्टाई करके 650 वर्ष पहले खेती के इस तरीके की शुरूआत की गई थी। आज यहां कुछ घर भी बन गए हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब यहां के लोगों के पास आमदनी तो दूर, खाने के लिए अनाज भी नहीं होता था। आज यहां के लोग न केवल समृद्ध हैं, बल्कि अनाज से ही अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। गुआन्शी राज्य की यह जगह आज इन्हीं राइस टेरेस के कारण दुनियाभर में चर्चित है। national geographic.com

# अहम फैसले

हाई कोर्ट ने हाल ही में सुनाए अपने एक अहम फैसले में, सीबीआई की विशेष अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने सोहारबुहीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई की कार्यवाही की रिपोर्टिंग या प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपितों द्वारा सनसनी फैलाने की चिंता मात्र, इस तरह के पाबंदी आदो जारी करने का पर्याप्त आधार नहीं है। इस तरह की पाबंदी नाजायज है और यह आदेश पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत का इस बारे में साफ कहना था कि प्रेस के अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करने वाले संवैधानिक अधिकार में निहित हैं। एक खुली सुनवाई की रिपोर्टिंग में प्रेस न केवल अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है, बल्कि आम जनता को इस तरह की सूचनाएं मुहैया कराने के बड़े मकसद को पूरा करती है। अदालत ने अपने फैसले में यहां तक कहा कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। खुली अदालत का मकसद ही यही है और मीडिया इस संदेश को जनता तक पहुंचाने का एक सशक्त मध्यम है। जाहिर है कि अदालत ने जो कुछ कहा, उसमें कोई भी बात गलत नहीं है।

अदालत ने अपना फैसला, संवैधान और कानून की रोशनी में ही दिया है। प्रेस की आजादी को लेकर जस्टिस मोहिते डेरे का यह अहमतरीन फैसला ऐसे दौर में आया है, जब मीडिया सत्ता के बेहद दबाव में है। अपना काम कर रहे पत्रकारों को लगातार धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। संदेह, सवालों और हरदम नये विवादों में घिरे रहे सोहारबुहीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत में चल रही है, जिसने बीते साल 29 नवम्बर को बचाव पक्ष की एक अर्जी के बाद मीडिया को अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया था। अदालत के इस आदेश को गैरकानूनी बताते हुए इसके खिलाफ दो याचिकाएं बांबे हाईकोर्ट में दखिल की गईं। एक याचिका बृहनमुंबई पत्रकार संघ ने तो दूसरी याचिका विभिन्न अखबारों और समाचार चैनलों की ओर से नौ पत्रकारों ने दायर की। बचाव पक्ष की इस दलील सुनने के बाद, जस्टिस डेरे ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामला कितना भी गंभीर हो, क्या आप उस प्रावधान के बारे में बता सकते हैं, जिसके अनुसार यह आदेश दिया गया है? अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो क्या किसी द्रायल कोर्ट जज को इस तरह का आदेश देने का अधिकार है? संवैधानिक मुद्दों पर जोर देने के साथ अदालत ने यह बात भी मानी कि सीबीआई के विशेष जज ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी का आदेश दिया है। गाहे-बगाहे कोई ना कोई दलील देकर कभी अभियुक्त, तो कभी अभियोजन पक्ष अदालत में मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में ये फैसला नजीर साबित होगा। इस मामले की सुनवाई सालों से चल रही है। कभी भी मीडिया की रिपोर्टिंग पर न तो कोई उंगली उठी और न ही पाबंदी लगी। पिछला किसी आधार के उस पर पाबंदी लगा दी गई, वह भी एक आरोपी की मांग पर। इस मोड़ पर मीडिया पर पाबंदी का कोई तुक नहीं है। यह मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने, सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया और मीडिया को उसके काम के लिए पहले सी आजादी प्रदान कर दी।



